लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16-31 जुलाई 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक-22

"समाज में रहकर समाज को हानि पहुंचाना, आत्महत्या कर लेने के समान है।"
: शरतचंद्र चट्टोपाध्याय

बंडारू दत्तात्रेय बने प्रदेश के 18वें राज्यपाल
➡ P2

प्रगति की रफ़्तार- उद्योग व व्यापार
➡ P3

खेत किसान की समृद्धि के लिए योजनाएं
➡ P5

कोरोना से जंग जारी, चिकित्सा की पुख्ता तैयारी
➡ P6

अति गरीब परिवारों के उत्थान का संकल्प
➡ P7

हरियाणवी कृतियों को मिलेगा 'सम्मान'
➡ P8

जन सहायक-आपका सहायक

ई-गवर्नेंस से एम-गवर्नेंस की ओर बढ़ते हरियाणा के लिए मोबाइल ऐप

विशेष प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री मनोहरलाल प्रदेश में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी शासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि नागरिकों का जीवन सहज, सरल व सुव्यवस्थित हो सके। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 'जन सहायक-आपका सहायक' मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिससे ई-गवर्नेंस से एम-गवर्नेंस की ओर तेजी से बढ़ा जा सकेगा।

इस ऐप के माध्यम से गवर्मेंट टू सिटीजन (जी2सी) और बिजनेस टू सिटिजन (बी2सी) सेवाओं की कहीं भी-कभी भी-किसी को भी डिलीवरी सुनिश्चित हो सकेगी। दरअसल राज्य सरकार इस ऐप के माध्यम से 'मोबाइल गवर्नेंस' की ओर तेजी से अग्रसर होने का प्रयास कर रही है।

नागरिक-केंद्रित सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हालांकि पहले से ही राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलें शुरू की गई है, लेकिन स्मार्टफोन के इस युग में सेवाओं को नागरिकों के घर द्वार तक पहुंचाने के लिए मोबाइल सेवा वितरण गेटवे की स्थापना की ओर यह बेहतर पहल है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से 42 विभागों की 551 सरकारी योजनाएं एवं सेवाएं सरल पोर्टल के माध्यम से लोगों को प्रदान की जा रही हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना 'मेरा परिवार-मेरी पहचान' शुरू की है, जिसके तहत परिवार पहचान पत्र कार्ड बनाया जा रहा है ताकि हर पात्र परिवार को राजकीय सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिल सके।

आपातकालीन सेवाओं के लिए मदद

'जन सहायक-आपका सहायक' ऐप एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें विभिन्न सरकारी सेवाओं, आपातकालीन हेल्पलाइन और अन्य सूचनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। ऐप के जरिए इन सेवाओं का लाभ सरलता से लिया जा सकेगा। ये सभी सेवाएं डायरेक्ट डायलिंग पर उपलब्ध रहेंगी।

- नागरिक आपातकालीन कॉल 112
- पुलिस के लिए 100
- एम्बुलेंस के लिए 108
- फायर के लिए 101
- स्वास्थ्य के लिए 104
- महिला हेल्पलाइन 1091
- बाल हैल्पलाइन नंबर 1098
- कोविड-19 हैल्पलाइन नंबर 1075

विभागीय जानकारी एवं मदद के लिए

गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं (जी2सी) जैसे सरल सेवाएं, विभागवार सेवाएं, प्रयोक्तावार सेवाएं, जन शिकायतें एवं आरटीआई को भी इस मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है।

विभिन्न विकास कार्यों के लिए निविदाएं, बिल भुगतान, यात्रा, नौकरियां, खेल आधारभूत संरचना और कौशल विकास समेत अन्य सेवाओं की जानकारी भी इस एप्लीकेशन के जरिए आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

हिंदी व अंग्रेजी में जानकारी

मोबाइल प्लेटफॉर्म यूजर्स की सुविधा के लिए इसे हिंदी और अंग्रेजी में डिजाइन किया गया है। इसके जरिए सभी तरह की गवर्नमेंट टू सिटिजन (जी2सी) सेवाएं एंड्रायड और एप्पल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।

इस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विभिन्न सेवाओं जैसे नई नौकरियों, निविदाओं व आगामी कार्य' मों की जानकारी, बिलों का भुगतान, प्रेस विज्ञप्तियां, कैलेण्डर, हरियाणा दूरभाष निर्देशिका जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकता है।

नोटः जन सहायक मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के उपरांत नागरिक इस पर अपना मोबाइल नम्बर व परिवार पहचान पत्र आई. डी दर्ज कर पंजीकरण कर सकते हैं।

मोबाइल वेब सर्च आसान

'जन सहायक-आपका सहायक' को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नागरिक सरल पोर्टल में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकता है अथवा जन शिकायत अनुभाग में अपने मुद्दों को उठा सकता है। जन सहायक मोबाइल ऐप पर सर्च करना बहुत आसान है। इसके जरिए सूचियों को ऊपर-नीचे किये बिना किसी भी शब्द जैसे कि नाम, श्रेणी एवं विभाग इत्यादि के माध्यम से सर्च की जा सकती है।

सुझाव साझा करने का प्लेटफॉर्म

उक्त मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए सुझावों का उपयोग संबंधित विभागों द्वारा बेहतरीन सेवा प्रदायगी के लिए किया जाएगा।

परिवार पहचान पत्र

एक संक्षिप्त परिचय

उक्त योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसके जरिए प्रदेश का कोई भी नागरिक राजकीय सेवाओं का घर बैठे फायदा ले सकेगा। इसके अमल में आने से किसी भी नागरिक को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

संबंधित पोर्टल पर अब तक 68 लाख 22 हजार, 528 परिवारों का डाटा (ब्यौरा) उपलब्ध हो चुका है।

इनमें से 48 लाख 39 हजार 182 परिवारों ने अपना डाटा का सत्यापित कर चुके है। इनमें कुल एक करोड़ 94 लाख 37 हजार सदस्य शामिल है। उन्हें 'परिवार पहचान पत्र' से सभी विभागों की लगभग 100 योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। 'पोर्टल' पर रजिस्ट्रेशन के बाद परिवार को सरकार की किसी भी योजना का लाभ पाने के लिए अलग से कोई प्रमाण पत्र जैसे कि आयु, जन्म, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट व अन्य पहचान संबंधित दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा।

हरियाणा सरकार की सब सेवाओं व योजनाओं को पीपीपी पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' पीपीपी पोर्टल, से लिंक की जाने वाली पहली योजना है। इसके अलावा इसके साथ 'वृद्धावस्था सम्मान भत्ता', 'विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन' व 'दिव्यांग पेंशन योजना' को जोड़ा गया है।

दरअसल यह कार्य इतनी तेजी से इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हरियाणा सरकार ने सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना- 2011 पर आधारित प्रदेश के लगभग 46 लाख परिवारों का 'डाटाबेस' पहले ही तैयार कर लिया था और उसे अब 'परिवार पहचान पत्र पोर्टल' से जोड़ दिया गया है।

बतादें कि जिस दिन कोई व्यक्ति किसी योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र हो जाएगा, उसे उसी दिन से उसका लाभ मिलने लगेगा। उदाहरण के तौर पर जिस दिन कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे यह संदेश मिल जाएगा कि वह वृद्धावस्था पेंशन पाने का पात्र हो गया है।

इसी प्रकार जैसे ही कोई युवा 18 वर्ष की आयु का हो जाता है तो उसके पास यह संदेश पहुंच जाएगा कि वह मतदान करने का पात्र हो गया है।

परिवार पहचान पत्र की भूमिका

यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य सभी सरकारी योजनाएं, सरकारी सेवाएं, उपलब्ध 'सब्सिडी' व अन्य सुविधाएं प्रदान करना है।

- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
- वृद्धावस्था सम्मान योजना
- दिव्यांग-पेंशन योजना

(शेष पृष्ठ 2 कालम 2 पर)

संपादकीय

तकनीक में क्रांति

गत कुछ माह की अवधि में हरियाणा में सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है और अब नए-नए 'ऐप' व 'प्लेटफार्म' के माध्यम से प्रशासन एवं राज्य सरकार हर क्षेत्र में जन-जन के साथ सीधे संपर्क में है। अब सब कुछ पारदर्शी भी है, सरल भी और अबाध भी। बात सिर्फ सरकारी योजनाओं की खिड़कियां खोलने की नहीं है। अब प्रदेश का किसान व आम आदमी अनेक खिड़कियों का स्वामी भी है। उसे 'माउस' की एक क्लिक या अपने मोबाइल फोन पर भी 'अपनी फसल, अपना ब्यौरा', 'मेरा पानी मेरी विरासत' और कहां, क्या व कब करना उचित होगा, आदि की जानकारी उपलब्ध है।

बीज से बाज़ार तक सरकार के साथ खड़ी है।

- फसलों के दाने-दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद
- अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
- गन्ने का भाव बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल तक किया गया, जो कि देश में सर्वाधिक है।
- खरीफ-2021 के लिए 13 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं। इनमें फसल की लागत मूल्य पर 50 से 85 प्रतिशत तक लाभ देना सुनिश्चित किया गया है।
- रबी सीजन 2021-22 के दौरान 84-72 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई तथा कुल 15942.50 करोड़ रुपए की अदायगी सीधे किसानों के खातों में की गई। किसानों को 72 घंटे के भीतर फसलों का भुगतान किया गया तथा निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर किसानों को नौ प्रतिशत की दर से लगभग एक करोड़ रुपए की ब्याज राशि का भुगतान भी किया गया।
- वर्ष 2020-21 में रबी व खरीफ फसलों की खरीद पर 29 हजार करोड़ रुपए की राशि का किसानों के खातों में भुगतान किया गया।
- सभी फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा', ई-खरीद पोर्टल शुरू किया है। इसके तहत किसानों को अपनी फसल बेचने, खाद, बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता घर बैठे मिल सकेगी।
- प्रदेश की 25 अनाज मंडियों में किसानों व मज़दूरों को 10 रुपए प्रति थाली की दर से रियायती भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 'अटल किसान मजदूर कैंटीन' शुरू की गई हैं।
- अब हर-हित रिटेल स्टोर/आउटलेट स्थापित किए जा रहे हैं।
- रोजगार कहां व कब उपलब्ध है, ये रास्ता भी नए प्रौद्योगिकी मंच प्रशस्त कर रहे हैं। चलिए स्वयं को इन ' तिकड़ी बदलावों के लिए तैयार करें।
- यही स्थिति कला, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र हैं। सभी लम्बित सम्मानों की अदायगी की गई है और लोक-साहित्य व युवाओं को अब विशेष नए अवसर प्रदान किए गए हैं।

उम्मीदें, यकीन में बदली हैं और विकास की गति ने भी नई रेतगी पकड़ी है।

- डा चंद्र त्रिखा

आबकारी विभाग द्वारा राजस्व की रिकार्ड वसूली

हरियाणा प्रदेश को आबकारी नीति के तहत 2021-22 की प्रथम तिमाही (अप्रैल से जून 2021) में आबकारी विभाग से 1751.04 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रह हुआ है। पिछले वर्ष इसी तिमाही के दौरान 1370.86 करोड़ एकत्रित किए गए थे, ऐसे में करीब 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश का राजस्व उत्पन्न करने वाला प्रमुख विभाग है। इसी वर्ष जून माह के दौरान विभाग ने 1004.70 करोड़ रूपए का संग्रह किया जबकि पिछले वर्ष

जून के महीने में केवल 586.32 करोड़ की वसूली की गई। इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के जून महीने में 71.36 प्रतिशत की राजस्व में वृद्धि हुई है।

डिप्टी सीएम ने हरियाणा सरकार की आबकारी नीति को अनुकरणीय नीति बताते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए तैयार की गई आबकारी नीति में नवीनीकरण या ई-निविदा के माध्यम से शराब की दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता बरतने का पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जहां लाइसेंस शुल्क के रूप में करीब 2910 करोड़ रूपए का राजस्व प्रदेश को मिला था वहीं इस वर्ष 2021-22 में खुदरा शराब ठेकों के कुल 1004 जोन में लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है जिससे विभाग को 3201.46 करोड़ रूपए का राजस्व मिला है।

विदेशी शराब के थोक व्यापार हेतु आवेदन आमंत्रित

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा राज्य में आयातित विदेशी शराब (बीआईओ) के थोक व्यापार हेतु 'एल-वन बी.एफ' लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हुए आवेदनों में से जांच करने व छंटनी के बाद कुल 14 आवेदकों को 'एल-वन बी.एफ' लाइसेंस के लिए पात्र पाया गया है।

नियमों का उल्लंघन करने पर केस दर्ज

लॉकडाउन अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने के कुल 90 मामले दर्ज किए गए। इन सभी मामलों में फैसला हो चुका है और पंजाब आबकारी हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2020 की धारा 72-ई के तहत कुल 63 करोड़ 15 लाख 17,600 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माना राशि में से अब तक कुल 6 करोड़ 56 लाख 59,853 रूपए की वसूली भी की जा चुकी है।

डिप्टी सीएम ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने बार-लाइसेंस के लिए फीस में करीब 8 प्रतिशत की छूट दी है। इस वर्ष बार-लाइसेंस धारकों को केवल 11 महीने की फीस अदा करनी होगी।

बंडारू दत्तात्रेय बने प्रदेश के 18वें राज्यपाल

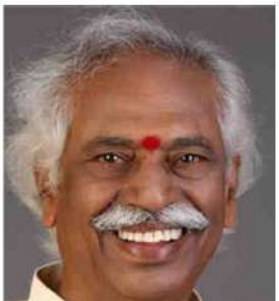

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का 18वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। श्री बंडारू दत्तात्रेय (74) को वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

उनका जन्म हैदराबाद में 12 जून, 1947 को हुआ। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की। पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय पहली बार 1991 में दसवीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। साल 1998 में वह दूसरी बार चुनाव जीते और वाजपेयी सरकार में शहरी विकास मंत्री बनाए गए। इसके बाद 1999 में फिर से वह जीत हासिल कर संसद पहुंच केंद्रीय रेल राज्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2014 में वह अपनी सिकंदराबाद सीट से चुनाव जीते और मोदी सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री श्रम एवं रोजगार (स्वतंत्र प्रभार) बनाए गए।

बंडारू दत्तात्रेय ने अपना राजनीतिक करियर संघ प्रचारक के तौर पर शुरू किया था। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते श्री दत्तात्रेय का हरियाणा से विशेष जुड़ाव रहा है।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक, मनोज चौहान
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

(पेज एक का शेष भाग)

परिवार पहचान पत्र.....

- विधवा और निराश्रित महिला पेंशन

पूरा विवरण इस 'पोर्टल' पर उपलब्ध है इसके अतिरिक्त 'सब्सिडी/लाभ' आदि का विवरण, विभिन्न विभागों, कृषि विभाग, श्रमिक-कल्याण बोर्ड (यूएलबी), महिला एवं बाल कल्याण, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण आदि 'सरल प्लेट फार्म' पर उपलब्ध कराए गए हैं।

कौन-कौन सा 'डाटा बेस' जोड़ा गया है?

- एचआएमएस
- हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा
- विवाह पंजीकरण

इस 'डाटा बेस' के प्रयोग से 'पीपीपी' वाले सभी व्यक्तियों के विवरण की पुष्टि हो सकेगी।

गैर-बीपीएल परिवारों को इससे क्या लाभ होगा?

- परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बीपीएल या गैर बीपीएल वर्गों के लोग सभी उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
- परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की 'ई-गवर्नेंस' की दिशा में की गई पहलकदमी है, जिसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को सभी योजनाओं, लाभ और सेवाओं के बारे में एक नए ढंग से जानकारी प्रदान करना है।

योजना के पूर्ण क्रियान्वयन से होने वाले लाभ-

- योजना, लाभ और सब्सिडी आदि त्वरित ढंग से मुहैया कराना
- कागजी कार्यवाही को न्यूनतम करना
- अलग-अलग योजनाओं के लिए एक ही प्रकार के दस्तावेज़ को बार-बार प्रेषित करने से छुटकारा

'परिवार पहचान पत्र' योजना का 'डाटा बेस' वास्तव में प्रार्थी की पारिवारिक जानकारी का एक अनूठा प्रामाणिक माध्यम है। इससे व्यर्थ के दस्तावेज़ों, परिचय पत्रों आदि के बार-बार प्रस्तुतिकरण से मुक्ति मिलेगी।

हमारा उद्देश्य यही है कि

हर नागरिक के घर-द्वार तक 'पेपर लैस' और 'फेस लैस' अर्थात् किसी भी प्रकार की कागजी कार्यवाही अथवा निजी उपस्थिति के बिना पूरी जानकारी मिले।

कहीं भी किसी भी समय सरकारी योजनाओं, 'सब्सिडी, सेवाओं व लाभों की सूचना प्राप्त हो।' यह पीपीपी कार्यक्रम धीरे-धीरे नागरिक को हर सुविधा/योजना की सूचना 'डिजिटल' रूप में देगा। कोई भी आवेदक कहीं से भी 'वेबसाइट' या 'पोर्टल' पर अपना आवेदन करने में समर्थ होगा। इसके अलावा भी भविष्य में उसे किसी नई योजना के लिए आवेदन करने या प्रमाण पत्र जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे पात्रता की शर्त पूरी होते ही सूचना मिल जाएगी कि उसके लिए कौन से नए अवसर का द्वार खुल गया है।

उदाहरणार्थ यदि उम्र के एक मोड़ पर वह वृद्धावस्था-सम्मान पेंशन का अधिकार हो गया है तो उसे घर बैठे ही पूरी सूचना स्वयमेव मिल जाएगी। उसके बैंक खाते में पेंशन राशि का भुगतान भी सीधे हो जाएगा।

- इससे लाभार्थी की पहचान में पूरी पारदर्शिता रहेगी।
- सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता की निशानदेही में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। 'पीपीपी' से सेवाएं प्रदान करने में डिजिटिलीकरण की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। सब कुछ पारदर्शी होगा और पूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध रहेगी।
- 'पीपीपी' का मूल उद्देश्य सरकार और जनता के बीच सीधा संपर्क जोड़ना है। इससे बीपीएल और एपीएल दोनों वर्गों को ही लाभ पहुंचेगा।
- कामकाज में दक्षता बढ़ेगी और सभी योजनाओं की मद में आवंटित राशि सही पात्रों तक आसानी से पहुंच जाएगी।

पीपीपी एक पासपोर्ट

हरियाणा सरकार की यह नई योजना वस्तुतः सामान्य नागरिक की जिंदगी को आसान बनाएगी। उसे बिना रोक टोक, बिना भ्रष्टाचार किसी भी जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठाने की सुविधा मिलेगी।

प्रदेश के **मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल** के जीवनदर्शन और कार्य संस्कृति का एक ही बीज मंत्र है

- अन्त्योदय-

अन्त्योदय का यह दर्शन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता व सुलभता के साथ आम आदमी तक उसकी अपनी ही जानकारी और सरकारी योजनाओं के बारे में उसकी पात्रता की जानकारी पहुंचाने के लिए समर्पित है।

वस्तुतः 'पीपीपी' एक ऐसा 'पासपोर्ट' है जो आपको ज़िंदगी की ऊंचाइयां छू लेने का सुलभ अवसर प्रदान करता है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार और नागरिक पूरी तरह आमने-सामने हैं।

यह योजना केवल आपके लिए सही दिशा-मार्ग ही नहीं खोलती बल्कि योजनाओं को आपके द्वार तक ले आती है।

निष्कर्ष यह है कि इस योजना के तहत 8 अंकों वाला पहचान पत्र आवंटित होगा, जो हर परिवार के लिए होगा। इसमें परिवार का ढांचा, प्रत्येक सदस्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण होगा। यह विवरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और व्यक्तिगत रूप में पुष्टिकृत होगा।

- हरियाणा सरकार का नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड- द सिटिजंस रिसोर्सेज इनफार्मेशन डिपार्टमेंट) इस पीपीपी कार्यक्रम को लागू करेगा। अतिरिक्त उपायुक्त स्थानीय स्तर पर जिला 'क्रिड अधिकारी' होंगे।
- डाटा-संग्रह का कार्य 'नागरिक सेवा केंद्रों (सीएससी)', 'सरल' केंद्रों, 'कम्प्यूटर ऑपरेटर केंद्रों' व जिले में समय-समय पर स्थापित अन्य ऐसे केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा।
- अब तक लगभग 69 लाख परिवार इस पीपीपी के माध्यम से जोड़े जा चुके हैं और प्रदेश की 2.6 करोड़ की आबादी इन्हीं नौ लाख परिवारों के अंतर्गत दर्ज है।
- 'सरल सेवाओं' व ऐसे ही 350 केंद्रों के माध्यम से विवाह-पंजीकरण, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और सामाजिक न्याय विभाग की सभी योजनाओं के क्रियान्वित किया जा रहा है।

-संवाद ब्यूरो

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने की सिफारिश की है। निर्धारित समय-सीमा को भी तर्कसंगत बनाने को कहा है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत प्रदेश सरकार अप्राकृतिक मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान रहा है। यह राशि संकट के समय में एक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।

प्रगति की रफ़्तार- उद्योग व व्यापार

संगीता शर्मा

हरियाणा सरकार राज्य में प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में दस इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाए गए हैं, जिनमें विश्वस्तर की सुविधाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग से एमएसएमई विभाग बनाया गया है। कोरोना महामारी के के बावजूद प्रदेश सरकार विदेशी निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रयास कर रही है। ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया व दक्षिण कोरियाई निवेशकों, अधिकारियों व प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके उनसे बातचीत की जा रही है।

उद्योग की अपार संभावनाएं

हरियाणा ऑटो कंपनियों और ऑटो-घटक निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। साथ ही, राज्य ने आईटी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है। हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात करने के मामले में भी अग्रणी है और यह आईटी/आईटीईएस सुविधाओं के लिए भी पसंदीदा गंतव्य है। हरियाणा में ऑटो विनिर्माण, कौशल विकास, आईटी और आईटीईएस, कृषि और कृषि-आधारित उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य व पशु विज्ञान, पर्यटन, इंटिग्रेटिड एविऐशन हब इत्यादि क्षेत्र में हरियाणा में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं।

प्रदेश पहले से ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी है और अब इन प्रगतिशील नीतियों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। ई-व्हीकल पॉलिसी जैसी राज्य की आगामी पॉलिसी व परियोजनाओं से निवेशकों को फ़ायदा मिलेगा। राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक नीतियों की दूसरे राज्यों में सराहना की जा रही है।

दुष्यंत चौटाला,
उपमुख्यमंत्री, हरियाणा

वर्तमान सरकार 'हरियाणा एक-हरियाणवी एक' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है और देशी व विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष सब्सिडी दी जा रही हैं। पिछले साढ़े छह वर्षों में हरियाणा डिजिटलीकरण की ओर बढ़ा है। हरियाणा को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए 'ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस', नए उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम जैसे कई प्रयास किए गए हैं। ये सभी कदम हरियाणा में निवेशकों को लुभाने के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा

निवेशकों को रियायतें

राज्य में निवेश करने वालों के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि खरीदने से लेकर और बुनियादी ढांचा खड़ा करने तक कई रियायतें दी जाती हैं। यही नहीं, निवेशकों को बिजली, संपत्ति कर व अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में काफ़ी सहूलियतें दी जाती हैं। राज्य सरकार प्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर कई परियोजनाएं जैसे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल आदि शुरू कर रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

एमएसएमई के विकास और हरियाणा में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय (एमएसएमई), पंचकूला को स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल की है। जिला स्तर पर, जिला एमएसएमई केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के तहत कुल 105 मामले जिला एमएसएमई केंद्रों द्वारा अग्रेषित किए गए, जिनमें बैंकों द्वारा 327.7 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में स्वीकृत किए गए।

खाद्य प्रसंस्करण समिति

राज्य सरकार ने हरियाणा कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2018 को अधिसूचित किया था। इस नीति के तहत राज्य स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण समिति (एसएलसी-एफपी) को अनुमोदित किया गया। कुल मिलाकर, इस नीति के तहत अब तक 195 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें सरकारी अनुदान घटक 28 करोड़ रुपए के साथ ही 165 करोड़ रुपए से अधिक की निजी भागीदारी शामिल है।

- 'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना' के तहत पंजीकृत करदाताओं को पांच लाख रुपए का बीमा।
- ''मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना'' के तहत दुकान के किसी नुकसान के लिए पांच लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का बीमा।
- ''प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना'' के तहत खुदरा विक्रेता और दुकानदार को 3,000 रुपए मासिक पेंशन।
- आर्थिक विकास एवं आजीविका के अवसर मुहैया करवाने तथा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ''हरियाणा उद्यम एवं रोज़गार नीति-2020'' लागू।
- उद्योगों की ''कॉस्ट ऑफ डुइंग बिजनेस'' को कम करने के लिए औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई।
- सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर।
- विदेशी निवेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने और विदेश निवेशकों से समन्वय स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है।
- सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, जिस पर निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए 45 दिनों में सभी प्रकार की मंजूरी ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है।
- प्रदेश में 2,409 करोड़ रुपए के निवेश से 53 बड़े एवं मध्यम उद्योग लगे। इनमें 97,623 लोगों को रोज़गार मिला।
- युवाओं को निजी क्षेत्र के उद्यमों में अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।
- 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने 71 ट्रेड्स में 40 औद्योगिक इकाइयों के साथ रोज़गार के लिए एमओयू किया।
- युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए जल्द ही ''उद्योग मित्र योजना'' शुरू।

अचल संपत्तियों की बाज़ार दर का निर्धारण करेगी समिति

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में अचल संपत्तियों की बाजार दर के निर्धारण के लिए एक नई नीति बनाई गई है, जिसके तहत एक समान स्थाई समिति का गठन किया जाएगा। समिति राज्यभर में सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की संपत्तियों की दरें तय करेगी।

समिति का गठन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा जिसे नई नीति के तहत नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। संबंधित मंडलायुक्त स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में विभागाध्यक्ष द्वारा मनोनीत मुख्यालय/जिले में एक विभागीय अधिकारी, जिसके प्रभार में भूमि या भवन का निपटान किया जाएगा, आयकर विभाग, भारतीय स्टेट बैंक और बीमा कंपनी द्वारा अधिसूचित/पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता शामिल होंगे और संबंधित जिला के जिला राजस्व अधिकारी इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

राजस्व विभाग के वित्तायुक्त व अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशल ने कहा कि नीति के अनुसार भूमि रिकॉर्ड यानी कि जमाबंदी, म्यूटेशन, खसरा गिरदावरी, अक्ष शिजरा, फील्ड बुक की प्रतियां संबंधित उपायुक्त द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। मंडल आयुक्त की राजस्व टीम द्वारा वेब-हैलरिस पोर्टल से स्वामित्व, खसरा संख्या सहित संपत्ति का शीर्षक ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि जमाबंदी के स्वामित्व कॉलम के अनुसार भूमि विशिष्ट करुकान (लंबाई और चौड़ाई यानी फील्ड बुक) के साथ पूर्ण खसरा संख्या (ओं) में है और किसी भी तरह से साझे में नहीं है।

आयकर

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभाग, भारतीय स्टेट बैंक और हरियाणा से संबंधित बीमा कंपनियों के पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं में से मूल्यांकनकर्ताओं को अधिसूचित/सूचीबद्ध किया जाएगा। विभाग पैनल में शामिल मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आचार संहिता भी अधिसूचित करेगा और संहिता का उल्लंघन होने पर उन्हें पैनल से बाहर कर दिया जाएगा।

नीति के अनुसार अध्यक्ष उस क्षेत्र, जहां भूमि स्थित है, में बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में निर्दिष्ट बाज़ार मूल्य का विवरण प्राप्त करेगा। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित कीमतों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाएगा।

यदि संबंधित बिल्डर/निजी संस्था संदर्भित भूमि के विक्रय विलेखों के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत निर्धारित नवीनतम कलेक्टर दरों की दोगुनी राशि या एक ही प्रकार की भूमि/अचल संपत्ति से संबंधित राजस्व सम्पदा में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान या उच्चतम राशि के दो विलेखों का औसत, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए तैयार हो तो पंजीकरण हेतु संबंधित विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उचित निर्णय लिया जा सकता तथा नीति में निर्धारित अन्य प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

कौशल ने कहा कि यदि भूमि के अंतिम मूल्य को अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो संबंधित सरकारी विभाग/बोर्ड आदि द्वारा पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के तहत निष्पादित हस्तांतरण विलेख पंजीकृत किया जाएगा।

-संवाद ब्यूरो

केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल के मुताबिक केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कुरुक्षेत्र में महाभारत व गीता से संदर्भित एक विश्वस्तरीय आभासी संग्रहालय बनाया जाएगा।

'फार्म्स' मोबाइल एप की सहायता से किसान भाई घर बैठे कस्टम हायरिंग सैंटरों का पता, उपलब्ध कृषि यंत्रों की सूची, किराया सूची आदि की जानकारी ले सकते हैं तथा बुकिंग भी करवा सकते हैं।

फूलों की खेती से सुकून और आमदनी

किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए लगन व मेहनत की बहुत जरूरत होती है। धूप, आंधी व बारिश आपका मनोबल कम नहीं कर सकती। यह कहना अंबाला कैंट के सरसेहड़ी गांव के बागवान हरीश सैनी का है। वह फूलों की नर्सरी के लिए ख़ासतौर से जाने जाते हैं। तीन साल से फूलों की सीडिंग प्रोसेसिंग में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके फूलों की पौध चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, हरियाणा, हिमाचल, सहारनपुर, देहरादून, उत्तराखंड में सप्लाई होती है।

बागवानी विभाग का सहयोग

बागवान हरीश बीस साल से नर्सरी का काम कर रहे हैं। सात साल से ईंटीग्रेडिट खेती कर रहे हैं। उनकी शहजादपुर के मघरपुरा गांव में शाशवता सीडिंग नर्सरी है। पहले वह साढ़े चार एकड़ में फूलों की नर्सरी कर रहे थे और अब साढ़े पांच एकड़ में बागवानी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पांच पॉलीहाउस तैयार किए हैं, जिसमें दो पॉलिथीन और तीन नेट के हैं। तीन पॉलिहाउस तैयार करने के लिए उन्होंने बागवानी विभाग हरियाणा से अनुदान मिला था, जबकि दो पॉलिहाउस खुद तैयार किए हैं। उनका कहना है कि बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, किसानों को उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना चाहिए।

मशीन का उपयोग

उन्होंने ढाई साल पहले इटली से 25 लाख की हाईटेक मशीन मंगवाई थी, जिससे बीजों की बिजाई और अन्य काम करने में आसानी हो गई। फूलों की पौध तैयार करने में मैनपावर बहुत लगती है और बीज बहुत बारीक व छोटे होते हैं। मशीन के माध्यम से जल्दी उगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पहले पूणे से उन्हें पौध खरीदकर लाने पड़ते थे, लेकिन मशीन से उनका काम आसान हो गया है। उनका कहना है कि खेती में क्षेत्र में हो रहे निरंतर बदलाव व नई तकनीक को किसानों व बागवानों को अपनाना चाहिए, इससे हम आमदनी को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गर्मियों में दस किस्म के फूल की पौध तैयार करते हैं और जबकि सर्दियों में फूलों की 25 किस्में होती है। इन दिनों वह सर्दियों के फूलों की तैयारी में व्यस्त है। मैरी गोल्ड, डायनथस , गजेनिया, पिटूनिया, डार्क फ्लावर, पैंसी, कैली, निमेशिया, जिरेनियम, कार्डेशियन, नोसुलस, डैजी, सालविया आदि अनेक किस्म की पौध तैयार करते हैं। इसके अच्छी व उच्चतम किस्म के बीज दिल्ली व पूणे से खरीदते है। इसके अतिरिक्त पोटेंड पौध भी तैयार करते है। हाईबिस्कस और मल्टी फ्लोरा की काफ़ी मांग है और थोक में यह 200-225 रुपए प्रति पौध बिकती है। उन्होंने बताया कि सॉयल लैस तकनीक के पौध भी उनके पास उपलब्ध है और यह काफी इपोर्टेड होते हैं।

लोगों को रुझान बढ़ा

उन्होंने बताया कि किस्म के हिसाब से एक फूल के पौध की कीमत तीन रुपए से आठ रुपए तक होती है। पौध को थोक में छोटा हाथी, थ्री व्हीलर और पिक अप में नर्सरियों में सप्लाई करते है। उन्होंने बताया कि नर्सरी में काम करने के लिए 11 पुरुष व 10-15 महिलाएं भी जुटी रहती हैं। इन लोगों को आवास की सुविधा भी दी गई हैं। हरीश सैनी ने बताया कि कोरोना काल में उनको अधिक नुक़सान नहीं झेलना पड़ा, बल्कि पौध की मांग बहुत बढ़ गई। जो लोग घरों में गमले नहीं रखते थे उन्होंने भी गमले रखकर फूल उगाने शुरू कर दिये। उन्होंने बताया कि वह पपीते की ताइवान की किस्म की पौध भी तैयार करते है। यह इसकी मांग अधिक है और यह पपीता अधिक रंगदार व मीठा होता है।

-संवाद ब्यूरो

सब्ज़ियों की खेती से मुनाफ़ा

कोरोना काल ने किसानों को अधिक हाईटेक बना दिया है। आए दिन किसान कभी कृषि विश्वविद्यालय, संस्थानों व समूहों की ऑनलाइन सेमिनार, कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं। व्हाट्स ऐप्प ग्रुप के माध्यम से भी किसानों की खेती से संबंधित समस्याओं का हल हो रहा है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव व अन्य जानकारियां हासिल होती है। इसकी मिसाल है रेवाड़ी के धवाना गांव में 'धवाना हर्बस फार्मर प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड' (किसान उत्पादक संगठन) के प्रधान ज्ञानी राम। वह सब्ज़ियों व फूलों की खेती करते हैं। जल्द ही उनके संगठन का कोल्ड स्टोरेज तैयार हो रहा है, जिसके माध्यम से लगभग 1,500 किसानों को फ़ायदा होगा।

ज्ञानी राम की 13 एकड़ ज़मीन है। तीन साल से अढ़ाई एकड़ ज़मीन में जैविक सब्ज़ियों की खेती करते है और पांच एकड़ ज़मीन पर फूलों की खेती करते हैं। एक एकड़ ज़मीन पर गेहूं की खेती करते है, जिसे अपने घर में उपयोग करते है। इसके अतिरिक्त अन्य ज़मीन पर वह सब्ज़ियों की खेती करते है। उन्होंने बताया कि खेती उनका पुश्तैनी व्यवसाय है, उनके बाप-दादा पारंपरिक खेती गेहूं व सरसों की करते थे, लेकिन वर्ष 2008 से उन्होंने बागवानी फसलों की खेती करनी शुरूकी, इससे उन्हें अधिक फ़ायदा हो रहा है। वह खीरा, तरबूज, गाजर, मूली, पालक, घीया, तोरी, टिंडा, टमाटर व अन्य मौसमी सब्ज़ियों की खेती करते हैं। इनकी बिक्री रेवाड़ी, गुरुग्राम, कोसली व रेवाड़ी की स्थानीय मंडी कुंड में करते हैं।

कोल्ड स्टोरेज से किसानों को फ़ायदा

उन्होंने बताया कि इस समय उनका कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम चल रहा है। अगले पांच महीने में यह बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हरियाणा सरकार का 80 प्रतिशत व किसानों का 20 प्रतिशत योगदान है। इसकी लागत 2.75 करोड़ रुपए है और इससे लगभग 1,500 किसानों को फ़ायदा होगा। इसमें ग्रेडिंग, पैकिंग व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि ग्रेडिंग होने से किसानों को सब्ज़ियों व फूलों के अच्छे दाम मिलेंगे। ज्ञानी राम ने बताया कि नवरात्र व दीवाली में फूलों की अच्छी कीमत मिलती है और पहले कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से फूल ख़राब हो जाते थे। अब दीवाली में उन्हें

अच्छे दाम मिल जाएंगे। वह बताते है कि इस समय वह फूलों की खेती में भी जुट गए है और यह खेती करके भी किसान अधिक आमदनी कमा सकते हैं।

सरकार की योजनाओं का उठाया लाभ

ज्ञानीराम ने हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग द्वारा चलाई अनेक योजनाओं का लाभ उठाया है और कहते हैं कि सरकार की योजनाओं से किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है और उनके खर्चे भी कम हो जाते हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार की मल्चिंग, टनल, बैबू स्केटिंग, नेटहाउस, वाटर टैंक व मशरूम खेती से मिलने वाली सब्सिडी समेत कई योजनाओं का लाभ उठाया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में हरियाणा सरकार के सहयोग से 'धवाना हर्बस फार्मर प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड' (किसान उत्पादक संगठन) का गठन किया। इस एफपीओ में 340 किसान शामिल है, जिसके अंतर्गत उनका धवाना एफपीओ खरीद केंद्र है। इसके माध्यम से किसानों के उत्पादों को बेचने में आसानी होती है और वे बिचौलिये के कमीशन से बच जाते हैं।

ज्ञानी राम खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं। उनके पास दो देसी गाय व तीन भैंस है। देसी घी 800 प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं। उनका कहना है कि बाज़ार में देसी घी मिलावटी बिक रहा है और लोग शुद्ध देसी घी खाना अधिक पसंद करते हैं। गोबर का प्रयोग जैविक खेती में करते हैं। उनका कहना है कि जैविक खेती के प्रति किसान धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं, हालांकि आरंभ में पैदावार कम होने से किसान इस खेती को करने से कतराते हैं।

हाईटेक हुए किसान

उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते अब ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से कार्यशाला व सेमिनार में भाग लेते हैं। इससे किसानों को नई-नई तकनीक सीखने को मिलती है। जिसे किसान अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। ज्ञानी राम कहते है कि एक्टिव फार्मर व्हाट्स ऐप्प ग्रुप के माध्यम से भी किसानों को खेती से संबंधित बिमारियों की सलाह मिलती है और नई जानकारी हासिल होती है। वह बताते है कि अब किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी फसलें उगानी शुरू कर दी है और उनके गांव में किसान 1,500 एकड़ ज़मीन पर सब्ज़ियों की खेती हो रही है।

-संगीता शर्मा

तिल उत्पादन: खर्च कम बचत ज्यादा

महेंद्रगढ़ के गांव मेघोट बिंजा के किसान परमानन्द शर्मा तिल की खेती करके अपनी जीविका चला रहे हैं। उन्होंने चार साल से तिल की खेती करनी प्रारंभ की हैं। इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। इस फसल में कम खर्च आता है व मेहनत भी कम करनी पड़ती है। बड़ी बात कम पानी लगता है।

वे साल भर का खर्च निकाल कर 7 लाख रुपए से ज्यादा की बचत कर लेते हैं। उनकी देखादेखी गांव के 16 अन्य किसानों ने भी तिल की खेती करना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने बताया कि एक एकड़ में बिजाई के लिए करीब डेढ़ किलो बीज लगता है। गर्मी के मौसम में ग्वार, मूंग, बाजरा और सर्दी के मौसम में सरसों, चना, गेहूं व मिर्च की भी खेती करते हैं।

कृषि विभाग के अधिकारी समय-समय पर फसल में लगने वाले रोग के उपचार के लिए आते रहते हैं। 2018 में 4 क्विंटल, 2019 में साढ़े 5 क्विंटल, 2020 में 4 क्विंटल तिल की पैदावार ली। अब की बार भी पांच क्विंटल से ज्यादा पैदावार का लक्ष्य है।

उन्होंने बताया कि तिल 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अच्छी फसल हो तो 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक भाव मिल जाता है। तिल की हाथों-हाथ बिक्री हो जाती है। लोग खाने में पशुओं के तेल के लिए तिल की बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उन्हें तिल को बेचने के लिए कभी बाजार नहीं जाना पड़ा।

परमानन्द शर्मा ने बताया कि वैसे तो तिल के उत्पादन के लिए बारिश से काम चल जाता है लेकिन फिर भी 70 दिन में चार या पांच तो पानी देने ही पड़ते हैं। जब तिल का पत्ता पीला हो जाता है व पते झड़ने लग जाते हैं तो फसल तैयार हो जाती है। कृषि वैज्ञानिक डॉ रमेश 15 दिन में खेत में आकर फसल की जांच करते हैं। फसल में ज्यादातर देसी खाद का उपयोग किया जाता है।

उन्होंने बताया कि जुलाई महीने में तिल की खेती करना फायदेमंद है। बल्लुई और दोमट मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर फसल अच्छी होती है व पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाता है। छिटकवां विधि से बुवाई करने पर डेढ़ किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। कतारों में बोने के लिए सीड ड्रील का प्रयोग किया जाता है तो बीज दर घट जाती है। बोने के समय बीजों का समान रुप से वितरण करने के लिए बीज को रेत (बालू), सूखी मिट्टी या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ मिलाकर बोना चाहिए।

-सुरेंद्र सिंह मलिक

राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा 'ग्राम दर्शन पोर्टल' पर उपलब्ध करवाया गया है। गांव में चल रही विकास परियोजनाओं और पंचायत द्वारा करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की जानकारी पोर्टल पर कभी भी देखी जा सकती है।

हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। दस हजार तक की आबादी वाले गांवों के लिए 'दीनबन्धु हरियाणा ग्राम उदय योजना' तथा इससे अधिक आबादी वाले गांवों के चौतरफ़ा विकास के लिए 'महाग्राम विकास योजना' बनाई है।

प्राकृतिक खेती करें, आमदनी बढ़ाएं

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों को आमदनी बढ़ानी है तो प्राकृतिक खेती की ओर भी जाना ही पड़ेगा। पंचकूला में आयोजित एक दिवसीय कृषि कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने खुशहाल बागवानी पोर्टल एवं फसल तुड़ाई के बाद प्रबंधन संबंधी जानकारी से युक्त पुस्तिका का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रगतिशील किसान सम्मान' हर जिले अनुसार एवं प्रदेश स्तर पर भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने प्रगतिशील किसानों का आह्वान किया कि वे हर वर्ष दस-दस और किसानों को ट्रेनिंग दें। इससे दो से तीन सालों में ही प्रगतिशील किसानों की संख्या कई गुणा बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि खेती है तो उद्योग है और तभी सर्विस सेक्टर

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब हरित क्रांति की आवश्यकता हुई तो हमने खाद्यान्न उत्पादन में नए आयाम स्थापित किए लेकिन इसके साथ-साथ रासायनिक खाद एवं पेस्टीसाईड का प्रयोग करके जमीन की उर्वरा शक्ति को कम कर लिया। वर्तमान समय के अनुसार हमें बदलना होगा, इसके लिए न केवल कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ानी होगी, बल्कि जल संरक्षण के प्रति भी जागरूक होना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हर एकड़ की फसल का डाटा अपडेट करने के लिए 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' योजना लागू की गई है। इसके अलावा जो किसान एग्रो फोरेस्ट्री अपनाएगा उन्हें भी प्रति एकड़ तीन साल तक दस हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे तीन वर्ष में लकड़ी की पूर्ति होगी और जंगल भी बचेंगे।

प्राकृतिक खेती की तकनीक

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा कि एक देशी गाय का पालन करने से हम 30 एकड़ कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र गुरुकुल के 200 एकड़ के फार्म में की जा रही प्राकृतिक खेती का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे न केवल उत्पादन बढ़ा, बल्कि मार्केट के मुकाबले अधिक दाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर व पेस्टीसाईड का इस्तेमाल करने वाले किसानों के खेतों की आर्गेनिक कार्बन का स्तर 0.3 से 0.4 से अधिक नहीं है, जबकि हमारे गुरुकुल में यह स्तर 0.8 से ऊपर है। यह केवल प्राकृतिक खेती करने से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से पानी, जमीन व पर्यावरण इन सभी का संरक्षण और किसान की आमदनी बढ़ना भी संभव है। इसके साथ प्राकृतिक खेती से उपजी फसलों का उपयोग करने से लोगों का जीवन भी स्वस्थ होगा।

-संवाद ब्यूरो

कपास की खेती का रखरखाव

प्रदेश में करीब दस जिले ऐसे है जहां कपास की खेती होती है। लगभग 95% क्षेत्र बीटी कपास के अधीन है। अगर देखा जाये तो कपास की लंबी अवधि 180-190 दिन की फसल होने के कारण विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा इसका नुकसान पहुंचता है। हरियाणा में सफेद मक्खी, हरा तेला, चुरड़ा व गुलाबी सूंडी कपास के मुख्य रस चूसक कीट है। लेकिन कपास की फसल में लगने वाले रस चूसक कीटों में सफेद मक्खी सबसे ज्यादा हानिकारक कीट है।

जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में सप्ताह में दो बार नियमानुसार कपास की फसल का निरीक्षण करें व 2 शिशु हरा तेला या 6-8 प्रौढ सफेद मक्खी प्रति पत्ता होने पर सिफारिश की गई कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। कपास की फसल में सफेद मक्खी की समस्या होने पर पहले दो छिड़काव नीमबिसिडिन, 300 पीपीएम 1 लीटर को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर यह छिड़काव करने के बाद भी सफेद मक्खी 6-8 प्रति पत्ता तथा हरा तेला 2 प्रति पत्ता से ऊपर दिखाई दे रहे है तो फलोनिकामिड 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सफेद मक्खी कीट सफेद रंग का होता है तथा यह आकार में बहुत ही छोटा होता है। यह ज्यादातर पत्तों की निचली स्तह पर रहकर रस चूसता है। जिससे पत्तियों से पोषक तत्व कम हो जाते है। ऐसे में पौधों की वृद्धि व कपास की पैदावार में कमी आ जाती है। सफेद मक्खी पत्ती मरोडक़ विषाणु को बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे में फैलाती है। वातावरण में ज्यादा नमी होने पर अगस्त-सितंबर में इनकी संख्या में वृद्धि होती है।

कृषि वैज्ञानिक मानते हैं की पोटाशियम नाईट्रेड के छिड़काव से पौधों में सूखे को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर फसल सूखे से ग्रस्त हो तो इसका छिड़काव करना बेहद जरूरी है। जब कपास की फसल 120 दिन की हो जाए तो 2 किलोग्राम पोटाशियम नाईट्रेड को 200 ली. पानी में मिलाकर दस दिन के अंतराल में दो छिड़काव करें। दवाओं के छिड़काव से संबंधी जानकारी के लिए विभाग से अवश्य संपर्क करें।

नरवाना के गांव खानपुर प्रगतिशील किसान रमेश कुमार बताते हैं की उनके गांव की बड़ी आबादी नरमा की उस फसल की बिजाई करती है जो नकदी होने के साथ-साथ बंपर पैदावार देती है। वर्तमान में 100 के करीब परिवार 400 से 500 एकड़ में नरमा की खेती कर रहे हैं।

कृषि अधिकारी संदीप बजाज ने बताया कि कपास की फसल को बीमारियों से बचाव के लिए मित्र कीटों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हानिकारक कीटों को मित्र कीट खाकर फसल को नुकसान होने से बचाते है। किसान को चाहिए कि वे खेत में उपयोगी मित्र कीटों को संरक्षण दें।

-संवाद ब्यूरो

खेत किसान की समृद्धि के लिए विशेष योजनाएं

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि इन कानूनों के लागू होने से किसानों को अपनी फसल इच्छानुसार मंडी या ओपन मार्केट में बेचने की छूट रहेगी। इस बार हरियाणा में किसानों ने सरसों की फसल ओपन मार्केट में एमएसपी से ज़्यादा मूल्य पर बेचकर अधिक मुनाफ़ा कमाया है।

केंद्र व हरियाणा सरकार ने किसानों के हित अनेक योजनाएं लागू की हुई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए उठाया गया बड़ा कदम है।

- किसानों को विभिन्न फसलों के बीज खरीदने पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है।
- गेहूं पर प्रति क्विंटल 1,000 रुपए, धान पर 1,000 रुपए, जौ पर 1,500 रुपए, सरसों पर 4,000 रुपए, तोरिया पर 4000 रुपए, चना व दालें 2,500 रुपए और बाजरा पर 1,500 रुपए की सहायता दी जाती है।
- कोई एक किसान कृषि यंत्र खरीदता है तो उसे 50 प्रतिशत तथा कई किसान मिलकर खरीदते हैं तो 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।
- यूरिया पर 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
- डेयरी स्थापित करने के लिए दुधारू पशुओं की खरीद करने हेतु बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- अनुसूचित जाति विशेष योजना के अंतर्गत 3 पशुओं की डेयरी, सूअर पालन व भेड़-बकरी पालन इकाईयां स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- किसानों को कृषि कार्यों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज़ बिना ब्याज उपलब्ध करवाया जाता है।
- सिंचाई के लिए जल संग्रह तालाबों के निर्माण पर सात लाख रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है।
- सिंचाई के लिए भूमिगत पाइपलाइन डालने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़, अधिकतम 60,000 रुपए प्रति किसान अनुदान राशि दी जाती है।
- 'फव्वारा संयंत्र प्रणाली' के तहत किसानों को 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।
- बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
- सोलर पम्प लगाने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- आम, अमरूद और सिट्रस फलों के बाग लगाने पर प्रति एकड़ 20 हजार रुपए सब्सिडी दी जा रही है।
- खेतों में उपयोग होने वाली बिजली 10 पैसे यूनिट की नाममात्र दर पर दी जाती है।
- किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर 12 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जाता है।
- मशरूम की खेती पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- हाइब्रिड सब्जी पौध तैयार करने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है
- वर्टिकल खेती पर 65 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
- मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी के बक्से की खरीद पर 85 प्रतिशत और उपकरण की खरीद पर 75 प्रतिशत अनुदान।
- 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत पात्र लघु और सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक की सहायता बैंक खातों में सीधे तीन किस्तों में उपलब्ध कराई जा रही है।

इस योजना के तहत अब तक हरियाणा के 19 लाख 42 हजार किसानों के खातों में 2,594 करोड़ रुपए डाले गये।

किसानों को सीधा लाभ

योजना	किसानों की संख्या	राशि का भुगतान (रुपए में)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	19 लाख 42 हजार	2,594 करोड़ 28 लाख
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	18 लाख 15 हजार	3,960 करोड़ 81 लाख
प्राकृतिक आपदा से फसल खराब मुआवज़ा	2,765 करोड़	
एकमुश्त निपटान योजना- सहकारी ऋण	4 लाख 10 हजार	1,314 करोड़ 31 लाख
भावांतर भरपाई योजना	4 हजार 187	10 करोड़ 12 लाख
सरचार्ज माफ़ी योजना-2019	1 लाख 12 हजार 300	23 करोड़ 80 लाख
भूमिगत पाईपलाईन स्कीम	1 हजार 957	8 करोड़ 34 लाख
कुल	42 लाख 85 हजार 444	10,676 करोड़ 66 लाख

'ई-गवर्नेंस' की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए पंचकूला के लिए एसएमएस के माध्यम से पेपरलेस बिलिंग का शुभारंभ किया गया है। पंचकूला में पानी के बिल सृजित करने के लिए किया गया है और इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

हरियाणा पुलिस को पासपोर्ट वेरीफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्र सरकार की ओर से प्रंशसा पत्र से नवाजा जाएगा। पिछले वर्ष हरियाणा पुलिस ऑथोरिटी ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन में बेहतरीन कार्य किया है।

कोरोना से जंग जारी, चिकित्सा की पुख़्ता तैयारी

कोरोना भले कमजोर हो गया हो लेकिन राज्य सरकार इसके प्रति किसी भी दृष्टिकोण से ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। आशंकित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पुख्ता प्रबंधन किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा रात दिन की गई कड़ी मेहनत का परिणाम है कि बहुत कम समय में कोविड से निपटने के व्यापक इंतजाम हुए हैं। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने की दिशा में गंभीरता से कार्य शुरू हुआ है।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कोविड से संबंधित सभी चिकित्सा उपचार संसाधनों जैसे वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजनयुक्त बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर की उपलब्धता, रेमेडिसिविर इंजेक्शन, एम्फोटेरिसिन, टोसिलिजुमैब की जानकारी ली, ताकि कोविड-19 के उपचार के लिए किसी भी उपकरण या दवा की कमी न रहे।

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने लॉजिस्टिक्स, अस्पतालों में उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं, दवाओं के स्टॉक, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बेड और भविष्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी से संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है इसलिए स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और स्टाफ को रेसनलाइज करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड और ऑक्सीजनयुक्त लैस बेड, आवश्यक दवाओं, निओनेटल वेंटिलेटर और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की जांच करने के लिए कहा ताकि वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जा सके। कोविड-पीडियाट्रिक मामलों के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि इन मामलों के इलाज के लिए आवश्यक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का पता लगाया जाए और उसके अनुसार आवश्यक व्यवस्था की जाए।

काबिलेजिक्र है कि राज्य की मौजूदा 20 सरकारी परीक्षण प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन 24500 टेस्ट और 22 निजी प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन 71900 टेस्ट करने की क्षमता है। अप्रैल 2021 में सेनिटेल सर्विलांस की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 15 दिन में प्रत्येक सेनिटेल साइट से 15 नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा पीजीआईएमएस, रोहतक में शीघ्र ही जीनोम टेस्ट के लिए प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। बताते हरियाणा में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.23 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.6 प्रतिशत है।

-मनोज प्रभाकर

कोरोना जागरूकता गीतों की सीडी लॉन्च

कोरोना काल में सरकार के साथ-साथ अनेक समाज-सेवी संस्थाओं ने अपने-अपने तरीके से आमजन को जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी धर्मवीर सिंह द्वारा लिखे और सुमेर पाल द्वारा गाये गए वैक्सीनेशन अभियान और कोरोना जागरूकता गीतों की सीडी को लॉन्च किया। ये गीत भी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे।

गीत के बोल है 'कोविशिल्ड और कोवैक्सीन, ये जान बचा री रै, टू डीजी भी गजब दवा, या साथ निभा री रै' और दूसरा है, 'कोरोना दुश्मन मानवता का--इसतै बचके रह्या करो, दो गज दूरी मास्क जरूरी, हाथ सफाई करया करो'।

मास्क लगाएं व भीड़ में जाने से बचें

कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी से बचने के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी छह फीट की सामाजिक दूरी बनाकर रहें। थोड़ी-थोड़ी देर बाद साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से 20 सैकंड तक अवश्य धोएं। यदि हाथ गंदे न भी हो तब भी हाथों को थोड़ी-थोड़ी देर बाद साबुन के साथ अच्छी तरह धोएं। घरों व कार्यालयों के दरवाजों के हैंडलों व अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं व हाथों को सैनिटाइज करना भी न भूले।

हाथों से मुंह, आंख, नाक, चेहरे आदि को न छूएं। सभी फेस मास्क अवश्य पहनें व हाथों से फेस मास्क को न छूएं। मास्क से मुंह व नाक अच्छी तरह से ढका होना चाहिए। स्वच्छता बहुत जरूरी है अतः सभी अपने घरों में व घरों के आस-पास सफाई व्यवस्था बनाए रखें। बाजारों में भीड़ में जाने से बचें और परिवार का एक ही सदस्य बाजार में या दुकानों पर सामान लेने जाएं।

बीड़ी-सिगरेट, पान, गुटका, खैनी आदि हानिकारक एवं जानलेवा है और इन्हें खाकर जगह-जगह थूकना भी कोरोना वायरस को फैलाता है। कोरोना वायरस के लक्षणों को देखते ही तुरंत अपनी जांच करवाए और अपनी बीमारी को न छुपाएं। सभी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखे व बढ़ाएं। सभी टीकाकरण करवाएं।

आदतें जिनसे बीमार हो सकती है किडनी

देश प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में 'किडनी फेलियर' के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। इसकी मुख्य वजह है अनियमित जीवनशैली, अनुचित खानपान और बिना डाक्टर की सलाह के दर्द निवारक दवाएं अधिक मात्रा में लेना। किडनी रोग विशेषज्ञ डा. एच्के अग्रवाल ने बताया कि इस तरह की व्याधियों की मुख्य वजह क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है।

धूम्रपान और शराब का सेवन

वैसे तो यह आदत कई बीमारियों की वजह बन सकती है लेकिन धूम्रपान एवं तम्बाकू का सेवन खासतौर पर फेफड़े संबंधी रोग होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। वहीं, इससे किडनी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है।

पेशाब रोककर रखना

रात भर में मूत्राशय पूरी तरह मूत्र से भर जाता है, जिसे सुबह उठते ही खाली करने की जरूरत होती है। लेकिन जब आलस की वजह से मूत्र नहीं त्यागा जाता और काफी देर तक रोके रखा जाता है तो आगे चलकर यह किडनी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।

जंक फूड

जंकफूड खाते रहना शरीर के लिए घातक हो सकता है। उसमें उपयुक्त होने वाले तेल व अन्य मसाले इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि उनका असर सबसे ज्यादा किडनी पर पड़ता है।

दर्द निवारक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल

बिना डॉक्टर की सलाह के केमिस्ट की दुकान से दर्दनिवारक दवाएं खरीदकर उनका सेवन किडनी के लिये खतरनाक हो सकता है। खासतौर पर बार-बार सिरदर्द की दवाई न लें। डिस्प्रिन गोली का सेवन भी डाक्टरी सलाह पर करना चाहिए।

पानी कम पीना

पानी कम मात्रा में पीने से किडनियों को नुकसान हो सकता है। पानी की कमी के चलते किडनी और मूत्रनली में संक्रमण होने का खतरा अधिक हो जाता है। साथ ही कम पानी से स्टोन का भी खतरा बना रहता है।

ज्यादा नमक का सेवन

कम या ज्यादा नमक खाना सेहत के लिए हानिकारक है। हमारे द्वारा भोजन के माध्यम से खाया गया 95 प्रतिशत सोडियम गुर्दों द्वारा मेटाबोलाइज्ड होता है। इसलिए नमक का अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में सेवन किडनी को कमजोर कर देता है।

बरसात में खान-पान का रखें विशेष ध्यान

बारिश की बूंदें जितनी मनोरम लगती हैं उतनी ही नुक्सानदेह हो सकती है। इस मौसम में पानी से पनपने वाली बिमारियां बढ़ जाती हैं। मगर यदि हम खान-पान को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें तो मौसम का आनंद उठाते हुए स्वस्थ रह सकते हैं। इस मौसम में तापमान में बार-बार बदलाव और उमस के कारण बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। इस कारण पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती। इंफेक्शन, एलर्जी, सर्दी-जुकाम, डायरिया, फ्लू, वायरल जैसी पानी और हवा से होने वाली बीमारियां हमें घेरे लेती हैं। जिनसे समय रहते बचना होगा।

नूंह को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दो चरणों में चलाए गए मलेरिया मुक्त मेवात अभियान में नूंह में वर्ष 2021 के दौरान 14 जून तक मलेरिया का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 'ग्रुप-सी' व 'ग्रुप-डी' की जो नौकरियां भरी जाएंगी, उनके लिए एक 'कॉमन एलिजिबिलिटी टैस्ट' की पंजीकरण करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 तक कर दी है।

सुकन्या समृद्धि योजना

बेटियां समाज का गौरव होती हैं। अगर इन्हें सही पालन-पोषण और अच्छी शिक्षा मिले तो अनेक बेटियां आकाश की बुलंदियों को छू सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा की धरती से हुई। इस कार्यक्रम के तहत देश और प्रदेश में कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गईं और परिणाम सबके सामने है।

आयकर में छूट

'सुकन्या समृद्धि योजना' भी 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही योजनाओं में से एक है, जो बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए वरदान है। इस योजना में जमा की गई राशि भविष्य में बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलवाने से लेकर उनकी शादी तक में आर्थिक रूप से मददगार साबित हो रही है। घरेलू बचत के लिए भी सरकार की यह एक अच्छी पहल है। सुकन्या समृद्धि खाता एक डाकघर से दूसरे डाकघर में निःशुल्क ट्रांसफर किया जा सकता है। जमा राशि पर लगने वाला ब्याज पूरी तरह से कर-मुक्त है और इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत छूट भी मिलती है। ऐसे में सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना के तहत अपनी बेटी का खाता ज़रूर खुलवाना चाहिए।

'सुकन्या समृद्धि योजना'

- इस योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक दो लड़कियों के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं।
- बेटी के जन्म से दस वर्ष तक की उम्र तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है।
- मात्र 250 रुपए से खाता खोला जा सकता है लेकिन साल में कम से कम एक हजार रुपए खाते में जमा होने चाहिए।
- साल में अधिकतम एक लाख 50 हजार रुपए जमा करवाए जा सकते हैं।
- सुकन्या समृद्धि खाता योजना में जमा राशि पर ब्याज की गणना सालाना की जाती है।
- अभिभावक इस खाते में 14 साल तक ही पैसे जमा करवा सकते हैं और 21 वर्ष में यह खाता मैच्योर हो जाएगा।
- बेटी के 18 वर्ष की होने के बाद उसकी उच्चतर शिक्षा के लिए तथा विवाह के समय जमा राशि में से आधा हिस्सा निकलवाया जा सकता है।
- खाता खुलवाने के लिए बेटी के जन्म का प्रमाण पत्र, अभिभावक के पते का प्रमाण तथा फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी या आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है।
- यह खाता पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों में खुलवाया जा सकता है।

गरीब परिवारों के उत्थान का संकल्प

प्रदेश में गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के तहत चिन्हित अति गरीब परिवारों को उनकी पसंद का रोजगार मुहैया कराने की दिशा में जिस तत्परता से कार्य शुरू हुआ है उससे लगता है आने वाले दिनों में इसके बेहतर परिणाम होंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि सरकार पर पहला हक गरीब व्यक्ति का होता है। इसी उद्देश्य के साथ यह योजना शुरू की गई है। सरकार का प्रयास रहेगा कि इसके अंतर्गत चिन्हित एक लाख परिवारों की सालाना आय कम से कम एक लाख रुपए हो जिससे उनकी गुज़र बसर सहज हो सके।

गौरतलब है कि प्रदेश के हर वर्ग में ऐसे अनेक परिवार है जिनके पास आजीविका का कोई विशेष जरिया नहीं है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो प्रति माह सरकारी राशन मिलने का इंतजार करते है। किसी परिवार में कमाने वाला नहीं है तो किसी को निम्नतम आय के अनुरूप दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल पाती। जरुरी नहीं है कि इन परिवारों के पास बीपीएल कार्ड हो। एपीएल कार्ड धारक भी गुरबत से दो-चार हो रहे हैं।

राज्य सरकार ने इस तरह के एक लाख परिवारों की पहचान कर उनका उत्थान करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने छह विभागों की एक संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

संयुक्त टीम में छह मुख्य विभाग जैसे विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में से एक-एक सदस्य शामिल होगा। टीम में शामिल प्रत्येक विभाग अपनी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत सूची बनाएंगे ताकि चिन्हित परिवारों के सदस्यों को इनकी जानकारी दी जा सके।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आय सत्यापन के आधार पर अब तक राज्य में सबसे कम आय वाले 30,000 गरीब परिवारों की पहचान की गई है, जिनकी आय 50 हजार रुपए से कम है। इनका डाटा संबंधित विभागों के साथ साझा किया जा चुका है। इसलिए अब इन परिवारों के सदस्यों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचने के लिए समर्पित प्रयास किए जाएंगे।

छह सदस्यीय टीम के सदस्य चिन्हित एवं सत्यापित परिवारों के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद करने के लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करेंगे। ऐसे सभी परिवारों के लिए एक प्रश्नावली भी तैयार की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 30 प्रमुख योजनाओं की जानकारी भी दर्ज होगी। ऐसे परिवारों से प्रश्नावली के जवाब लिए जाएंगे, जिनसे पता लग सके कि उनकी किस कार्य में अधिक रुचि है।

इस संवाद के आधार पर टीम के सदस्य आय बढ़ाने की योजना को अंतिम रूप देने की दिशा में पहल करेंगे। इसके अलावा इन 30 योजनाओं के जानकारीयुक्त पम्फलेट भी इन परिवारों में वितरित किए जाएंगे ताकि उनमें जागरूकता बढ़ाई जा सके।

संबंधित परिवारों से ली गई जानकारी के आधार पर उनके पसंद के काम के अनुसार परिवारों की अलग से सूची बनाई जाएगी। जो परिवार पहले से कोई काम कर रहे हैं, जिसमें उनकी आय कम है, तो उसी कार्य में उनकी आय किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इस पर प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए राज्य सरकार एमएमएपीयूवाई क्रियान्वित कर रही है। योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए छह सदस्यीय टीम के अलावा जोनवार समिति भी गठित की जाएं। राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय टास्क फोर्स पहले ही गठित की जा चुकी है।

-संवाद ब्यूरो

सेक्टर की तर्ज पर गांवों में विकसित होंगी मॉडल कॉलोनी

प्रदेश के ग्रामीण इलाके में भी शहरी सेक्टरों की तर्ज पर कालोनियां विकसित की जाएंगी। पानीपत जिले के इसराना गांव में जननायक चौ. देवीलाल मॉडल कालोनी की आधारशिला रखी गई है। इसराना प्रदेश का पहला ऐसा गांव होगा जहां 48 एकड़ में पहली मॉडल कॉलोनी (ग्रामीण सेक्टर) विकसित करने की शुरुआत की गई है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि शहरी सेक्टर के समान सुविधाओं से युक्त इस कालोनी में 180 गज से लेकर 500 गज तक के प्लाट उपलब्ध होंगे। पार्क, बिजली सब स्टेशन और शॉपिंग सेंटर भी होगा कॉलोनी में इसराना में 48.5 एकड़ मे स्थापित की जा रही इस कॉलोनी में 6.4 एकड़ में पार्क बनाए जाएंगे। 14.85 एकड़ में रास्ते और 26.80 एकड़ में निर्मित क्षेत्र होगा। 2 एकड़ में सामुदायिक केंद्र, 0.2 एकड़ में बिजली सब-स्टेशन, 0.26 एकड़ में डिस्पेंसरी, 3.6 एकड़ में शॉपिंग सेंटर, 0.3 एकड़ में पेट्रोल पंप, 0.4 में पुलिस चौकी और 0.62 एकड़ में प्राइमरी स्कूल भी होगा।

गांव में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह शुरुआत की गई है। इस तरह की मॉडल कॉलोनी नारनौद और बहादुरगढ़ में भी विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसराना की इस मॉडल कॉलोनी में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी मूल इसराना वासियों की रहेगी और 40 प्रतिशत हिस्सेदारी सबके लिए ओपन होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग सफल रहा तो इसी की तर्ज पर 200 एकड़ में साथ लगती ज़मीन पर और कॉलोनी बसाई जाएगी।

मिशन ओलंपिकः गोलकीपर सविता पूनिया

भारतीय महिला हॉकी टीम को इस बार पदक की उम्मीद है। टीम की उप कप्तान एवं गोलकीपर सविता पूनिया के बुलंद इरादों से वर्ष 2017 में एशिया कप और 2018 में एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था।

सविता पूनिया जिला सिरसा के गांव जोंधका की रहने वाली हैं। उन्होंने गांव की पगडंडियों को पार कर हॉकी को नई दिशा दी है। उनकी बेहतरीन उपलब्धियों को देखते हुए सरकार ने उन्हें 'अर्जुन अवार्ड' से सम्मानित किया है।

तैयारियों को लेकर टीम के बारे में

टीम में आठ अनुभवी खिलाड़ी हैं। रियो के बाद हमने काफी सुधार किया है। रियो में शायद इतने बड़े मंच से खेलने का अनुभव न होने से जीत हासिल नहीं कर पाए लेकिन अब की बार पदक की बड़ी उम्मीद लेकर हमने तैयारी की है। इन 5 वर्षों के दौरान हमने पूरा मंथन किया। जिन गलतियों के कारण हम मेडल नहीं जीत पाए थे विशेष तौर पर उस पर ध्यान केंद्रीत किया है

कोविड के दौरान अभ्यास प्रभावित

कोविड के दौरान अभ्यास के लिए जनवरी में अर्जेंटीना व मार्च में जर्मनी के साथ मैच खेले। जिनमें कई मैच काफी क्लोज रहे। कोरोना काल में रियो ओलिंपिक में हुई गलतियों को सुधारने करने का मौका मिला। अबकी बार टीम निश्चित रूप से किसी न किसी परिणाम पर जरूर पहुंचेगी।

बड़ी जिम्मेदारी

गोलकीपर को आम खिलाड़ी से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस दौरान वह अपने जूनियर के साथ अनुभव शेयर करती है। वैसे हर खिलाड़ी का खेल में अहम रोल रहता है।

सरकार की तरफ से सहयोग

शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से इतना सहयोग मिल रहा है। ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयारी के लिए पहले ही राशि दी गई है। खेल मंत्री संदीप स्वयं खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछते रहते हैं व समय-समय पर खिलाड़ियों से संवाद करते रहते हैं।

आप किसे आदर्श मानती हैं

मैं अपने दादा स्वर्गीय रणजीत सिंह को अपना आदर्श मानती हूं। इन 17 वर्षों में मैं 10 दिन से ज्यादा घर पर नहीं रही। हमेशा इंडिया कैंप में हॉकी पर ध्यान दिया है। अब मेहनत का परिणाम देने का समय आ गया है इसके लिए भारतीय महिला हॉकी टीम तैयार हैं।

किस टीम से मुकाबला मानती हैं

आस्ट्रेलिया, जर्मन, हॉलेंड की टीमें अच्छी हैं। ओलिंपिक में इंडियन टीम का पहला मैच नीदरलैंड से होगा। नीदरलैंड की टीम भी बेहतर है लेकिन हम पूरे हौसले के साथ खेलने को तैयार हैं।

सुरेन्द्र सिंह मलिक

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वे अपना कारोबार और स्व-रोजगार स्थापित कर सकें।

अटल भूजल योजना का प्रमुख उद्देश्य हरियाणा में भूजल संसाधनों का हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क तैयार करना है और यह राज्य में भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए सामुदायिक संस्थानों के निर्माण को भी प्रोत्साहित करता है।

तीतर पूंछ जैकाना

बसई, गुरुग्राम
बर्ड्स आफ हरियाणा

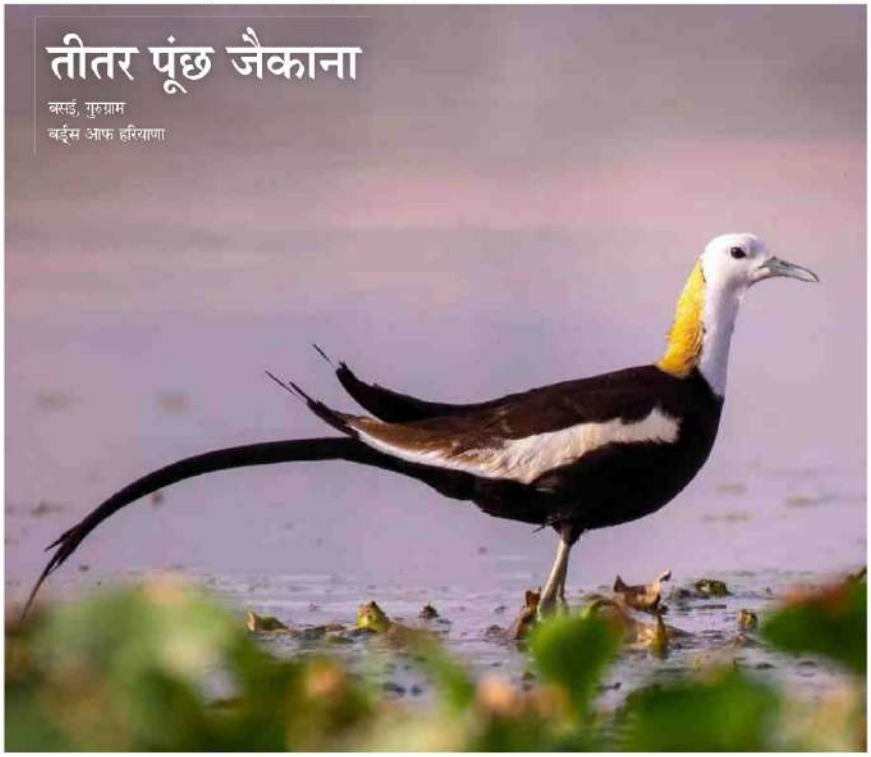

कला नीति से निखरेगी हरियाणवी कला

प्रदेश में कला, संस्कृति व लोक विधाओं को नए आयाम देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कलाकारों के हित में कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा कला नीति तैयार किए जाने बारे निर्देश दिए गए हैं। जिसे अमलीजामा पहनाते हुए विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश द्वारा कला नीति तैयार करवाई जा रही है।

कला परिषद के मुख्यालय कला कीर्ति भवन में निदेशक संजय भसीन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें हरियाणा कला परिषद के मण्डलों के अतिरिक्त निदेशक गजेंद्र फौगाट, महावीर गुड्डू तथा नागेंद्र शर्मा ने भाग लिया।

संजय भसीन ने कहा कि विभाग द्वारा तैयार कला नीति कलाकारों के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। कलानीति में विभिन्न प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक आयोजनों, समारोह, उत्सवों, कलाकारों की ग्रेडिंग तथा आपातकाल में की जाने वाली आर्थिक सहायता सम्बंधित विषयों को शामिल किया गया है।

गजेंद्र फौगाट ने कहा कि प्रदेश में लोक कलाकारों की कोई कमी नहीं है, किंतु उन्हें उनकी प्रतिभा दिखाने के उचित अवसर तथा आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता। ऐसे में प्रदेश की कला नीति न केवल लोक कलाकारों को मंच मुहैया करवाते हुए आर्थिक सहायता करेगी, अपितु लोक विधाओं को भी विस्तार मिलेगा।

महावीर गुड्डू ने कहा कि कला नीति से हरियाणा राज्य के लोक एवं गुणी कलाकारों को अवश्य लाभ होगा। राज्य सरकार की नीति के अनुसार अन्य प्रदेशों की तरह हरियाणा की सांस्कृतिक छटा भी पूरे भारतवर्ष में बिखरती नजर आएगी।

कलाकार स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग दें: सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में फिल्म सिटी खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए 50 से 100 एकड़ तक भूमि निर्धारित की गई है। हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर हर साल एक अवार्ड दिया जाएगा और कला के प्रोत्साहन के लिए हरसंभव सहायता भी दी जाएगी। उन्होंने कलाकारों से कहा कि कला में फूहड़ता को किसी भी नजरिए से वाजिब न माना जाए और इसका विरोध करें। ऐसे कलाकार भीड़ तो जुटा सकते है लेकिन स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहयोग नहीं कर सकते।

हरियाणवी कृतियों को मिलेगा 'सम्मान'

हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2021 से हिन्दी तथा हरियाणवी भाषा की विभिन्न विधाओं में 14 नए युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार शुरू किए जा रहे हैं, जिसके तहत विजेताओं को 31-31 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

अकादमी के निदेशक डॉ. चन्द्र त्रिखा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो अकादमी के अध्यक्ष भी हैं, के विशेष निर्देशों पर राज्य में दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार की संख्या दो से बढ़ाकर चार की गई है। इसके अतिरिक्त, अब इस पुरस्कार के तहत विजेता को 50,000 रुपए की बजाय एक लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणवी भाषा के माध्यम से प्रदेश के लोक साहित्य एवं संस्कृति के प्रति उल्लेखनीय योगदान के लिए लोक कवि श्री दयाचन्द मायना के सम्मान में एक नया साहित्यकार सम्मान भी अनुमोदित किया गया है। उन्होंने कहा कि अकादमी द्वारा यह सम्मान वर्ष 2021 से लोक साहित्य एवं संस्कृति वर्ग के अंतर्गत 'लोक कवि दयाचन्द मायना सम्मान' के नाम से आरंभ किया जा रहा है। इस सम्मान की राशि दो लाख रुपये होगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति उपरांत अकादमी द्वारा वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 के लम्बित साहित्यकार सम्मान (कुल 38), श्रेष्ठ कृति पुरस्कार (कुल 37) तथा पाण्डुलिपि पुरस्कार (कुल 75) योजनाओं के परिणामों की घोषणा भी गत दिवस की गई थी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत इन सभी पुरस्कारों की राशि विजेताओं के बैंक खातों में सीधे जमा करवा दी गई है।

सुण छबीले-बोल रंगीले

-अरै छबीले कित ज्योड़ा तुड़ाया सै?

-भाई रंगीले माणस तो मं एक, और काम होगे घणे। सारा दिन पुखाड़-सी पाटी रै सै।

-इसी के बात होई?

-पहल्यां कोटे में जाणा, राशन आया सै। फेर वो गैस सिलेंडर आला टेंपो आण आला सै, सिलेंडर लेणा। डांगरां ताहीं न्यार-पाणी करना और बाखर रेधना धरना।

-के बात सारे काम तनै ए करणे सैं। धरआली कित गई?

-उसकै हरकत होरी सै। वो डिस्पेंसरी में दवाई लेण गई।

-तै फेर राशन खातिर कार्ड किसे और तैं दे देता। वो ले आवता दो रुपए किलो आले गेहूं।

-छबीले ईब वो जमाना कोन्या रहा। जिसका राशन कार्ड होगा उसै नै राशन मिल्लैगा। गुठे की पछाण करैं सैं। पहल्यां तै तेंरे बरगे भी कोटे आले तै मिल मिलाके चोरी की चोरी घरां तरवा लिया करते। और तै और कई बै तो पूरा कोटा का कोटा ए गोल हो ज्याया करता। सुणा तो न्यू बी करते अक गेहूं के ट्रक के ट्रक मिल्लां में पहुंच जाया करते। पब्लिक जाओ भाड़ में। ईब वो घपड़चौथ कोन्या होती। एक एक दाने का हिसाब कम्प्यूटर में होवै सै। खास बात यो सै अक दो दिन आगै-पाछै दाणे सबनै मिलै सै।

-रही बात छबीले सिलेंडर की। ईब सुख होरया सै। पहल्यां म्हारे पड़ौसी एक सिलेंडर लेण खातिर शहर में जाया करते। उड़ै लैन में लागया करते। बख्त तैं जाते तो मिल जाता, नहीं तै उल्टे आ जाया करते।

- इस सरकार में म्हारे ताही भी गैस कनेक्शन मिलग्या। नहीं तो तेरी भाभी कीकर काट-काटकै सिर पै भरोटे ढोया करती। खाणा पीणा कम था और मेहनत मजूरी ज्यादा। ईब ये गैस सिलेंडर बारणे आगै तारकै जावैं सैं। भा के भा। पहल्यां ब्लैक में भी ना मिल्या करते। सोचण आली बात यो सै, ईब इतनी गैस कड़े तैं आगी,पहल्यां कोन्या आई।

-बात तो तेरी ठीक सै रंगीले, पहल्यां आली सरकार ये काम क्यूं नहीं कर पाई? उसै टैम के नेता ईब ताहीं भी कुछ कुछ बात मारैं सैं।

-अरै छबीले, छाज तो बोलै, छालणी भी के बोलै। वे तो आपणे टैम में वोए काम करया करते अक 'ठाडा मरै रोवण दे ना, खाट खोस ले सोवण दे ना।'

-अच्छा चालूं सूं, सप्लाई का पाणी आण आल्ला सै। डांगरां ताहीं पाणी प्याण का टैम बी हो लिया। छबीले पहल्यां पाणी खातर डांगरां नै बाहर जोहड़ पै ले ज्याया करते। उड़ै डांगर कै तो जोहड़ में तै लिकड़कै नहीं दे थे, लिकड़ जाते तै खेतां कान्या थोबड़ा ठा लिया करते। रे रे माटी हो जाया करती।

-सुख तो भतेरे होरे सैं रंगीले। पर इन सुखां की वजह तैं देही हराम हो ली। सारे दिन गाम में बिजली इसी रह सै अक खेत-क्यार कान्या जाण नै जी नहीं करता।

रंगीले की गोज में पड़े फोन पै मैसेज की ट्यून बोलज्या सै। फोन देख्या और बोल्या- ले भई छबीले खाते में पिल्सण आगी। मैं चालूं सूं।

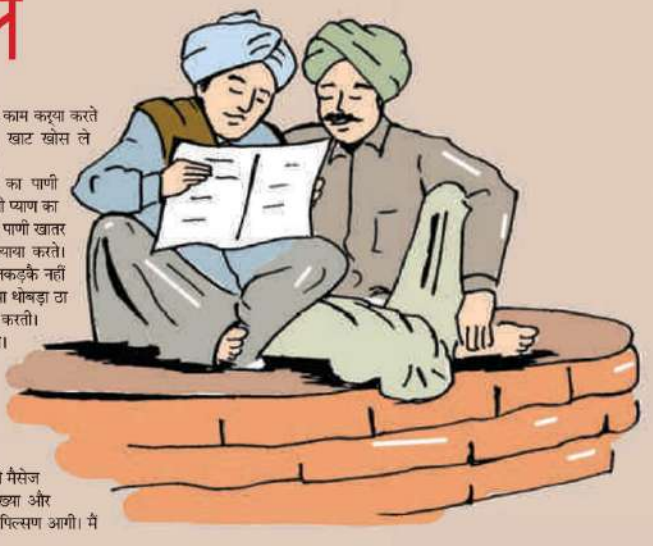

-मनोज प्रभाकर

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए, कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com